भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1567
जिसका उत्तर 4 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
13अग्रहायण, 1946 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन को वहनीय बनाने के लिए राजसहायता

1567.श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में सुधार करने के लिए कोई नए उपाय किए हैं;
(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए स्मार्टफोन और मोबाइल डाटा को और वहनीय बनाने के लिए राजसहायता अथवा प्रोत्साहन शुरू करने की योजना बना रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): ग्रामीण भारतमें डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीणडिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) तक पहुंचना था।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 79 वेंदौर (जुलाई, 2022 से जून, 2023) में 'व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण' (सीएएमएस)आयोजित किया और उनकी रिपोर्ट के आंकड़ों से भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रोंमें डिजिटल साक्षरता में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक रुझान का संकेत मिलता है। उक्त रिपोर्टसे और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट-फोन के उपयोग, इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल जुड़ावमें उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कियागया । पीएमजीदिशा योजना समाप्त हो गई है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक देश भर में 6 करोड़ के तय लक्ष्य की तुलना में 6.39 करोड़ व्यक्तियोंको प्रशिक्षित किया गया था।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,भारत सरकार ने बड़े पैमाने परइलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण (एलएसईएम) केलिए उत्पादनसंबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) सहित विभिन्नयोजनाओं के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहनदिया है।यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइलफोन विनिर्माण और असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित निर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादनसंबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करती है।

एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना से प्रेरितहोकर, पिछले एक दशक में मोबाइल फोन का उत्पादन काफी बढ़ गया है। मोबाइलफोन का उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 4,20,000 करोड़ रुपये हो गया है (उद्योग अनुमान)। उद्योग के अनुमान केअनुसार, घरेलू मांग का 99.2% घरेलू उत्पादन से पूरा किया जा रहा है।

सरकार द्वारा की गई उपरोक्त पहलों के कारण, भारत मात्रा केमामले में दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ाविनिर्माता बन गया है। उद्योग के अनुमानके अनुसार, मोबाइल फोन का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 1,566 करोड़ रुपये से बढ़करवित्त वर्ष 2023-24 में 1,20,000 करोड़ रुपये होगयाहै ।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 21.11.2024 की रिपोर्टबताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 525.60 मिलियन वायरलेस ग्राहक हैं और शहरीक्षेत्रों में 628.12 मिलियन वायरलेस ग्राहक हैं। डेटा कीकीमत मेंकाफी कमी आई है। यह दूरसंचारक्षेत्र में सुधारों और नवाचार का परिणाम है।

****